वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

2013-14

भारत रूरल लाइवलीहुडस फाउंडेशन

विवरण

अध्याय	अध्याय का नाम	पृष्ट क्रमांक
1	परिचय	1
2	पंजीयन की स्थिति	1
3	बी आर एल एफ के उद्वेश्य	1
4	विस्यगत केंद्रित	3
5	भौगोलिक केंद्रित	3
6	शासन	4
7	पारदर्शिता तथा जवाबदेही	4
8	संपादित मुख्य गतिविधियां(2013.14)	4
अनुसारणी–I अनुसारणी–II	बी आर एल एफ एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन बी आर एल एफ वित्तय अंकेक्षण समझौता ज्ञापन	

परिचय

भारत रूरल लाइवलीहुडस फांउडेशन (बी आर एल एफ) एक स्वतंत्र सोसायटी पंजीयन है जो कि केंद्र सरकार के साथ साझेदारी में नागरिक समाजकार्य के विकास की गतिविधियों में बढोतरी हेतु कटिबद्ध है। बी आर एल एफ एक स्वायत्त संरचना है ओर जो कि सोसायटी रजिस्टेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है।

बी आर एल एफ को सिविल सोसायटी एक्शनस/सामान्य समाज की गतिविधियों को सरकार की साझेदारी के साथ प्रेरित व समन्यवयन करने हेतु स्थापित किया गया है, जिससे की मध्यभारत के क्षेत्रों, विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के जीवन व आजीविका के मुद्दों पर परिवर्तन लाया जा सके। ज़मीनी स्तर पर हो रहे प्रयासों में मदद के साथ,समुदाय विशेषकर आदिवासी समुदाय को सशक्तीकरण की ओर लाकर उनके प्रयासों को इस स्तर तक लाना जहां वे कार्यक्रम की सामग्री और रणनीति दोनों ही संदर्भ में नवीनता को प्राप्त कर सकें। यह नवीनता अनेक दिशाओं में हो सकती है – तकनीक, सामाजिक लामबंदी की पहुंच, स्थानिय संस्थानों का निर्माण, निर्माण में साझेदारी, तकनीकों का प्रबंधन आदि। रणनीतिक रूप में, बी आर एल एफ के द्वारा सहयोग किये जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम को यह एक सामान्य सुविधा मिलेगी की वे बैंक व शासन केंद्र द्वारा संचालित ग्रामीण विकास व आजीविका कार्यक्रमों के लिये बहुतायत में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त करे।

मार्च 16, 2012 को भूतपूर्व वित मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गए बजट उद्घोषण के पैरा III में भारत रूरल लाइवलीहुडस फांउडेशन की स्थापना को प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्तावित किया जाता है कि भारत रूरल लाइवलीहुडस फांउडेशन की स्थापना की जाए। यह संस्थापन भारत में सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा किये जा रहे लोक हितैषी कार्यों को जो कि विशेषकर चिन्हित आदिवासी बहुल 170 जिलों में संपादित किये जा रहे हों, सहयोग एवं समर्थन प्रदान करेगा तथा बढोतरी की ओर ले जाएगा। निजी ट्रस्ट व लोक हितैषि संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे संस्थापन के साथ साझेदारी स्थापित करें। संस्थापन अपना कार्य पूर्ण रूप से पेशेवर तरीके से संपादित करेगा। इस घोषणा के उपरांत केंद्रिय मंत्रीमंडल की बैठक जो कि 3 सितंबर 2013 को आयोजित की गई थी जिसमे यह निर्णय लिया गया कि बीआरलफ का गठन किया जाये जो सरकार की साझेदारी में सिविल सोसायटी संगठन द्वारा किये जा रहे लोक हितेषी कार्यों को बढा एवं समर्थन प्रदान करेगी।

पंजीयन की स्थिति

भारत रूरल लाइवलीहुडस फांउडेशन का पंजीयन 10 दिसंबर 2013 को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त संरचना के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया।

बी आर एल एफ के उद्देश्य

भारत रूरल लाइवलीहुडस फांउडेशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैः

1. सिविल सोसायटी संगठनों के सामाजिक गतिविधियों का सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना जिससे मध्यभारत के आदिवासी क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं के आजीविका में परिवर्तन लाया जा सके।

2. सिविल सोसायटी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कराना जिससे की उनके संस्थागत व मानव संसाधन के मदों का खर्च निकल सके तथा तयशुदा विकास के कार्यों, छोटे स्तर के सामाजिक संस्थाओं के संस्थागत मज़बूती में निवेश व उनकी कुशलतावर्धन का कार्य व ज़मीनी स्तर पर कार्यरत व्यवसायिक मानव संसाधनों के विकास भी संभव हो सके।

   बी आर एल एफ मुख्यतयाः इन मदों पर वित्तिय सहायता प्रदान करता है :

   i. सिविल सोसायटी संगठनों के मानव संसाधन व संस्थागत विकास व्यय जिससे ज़मीनी स्तर पर प्रमाणित गतिविधियों को बढावा दिया जा सके। इसके अंतर्गत पोषित संस्था को कार्यक्रम के कुल खर्च का एक हिस्से की व्यवस्था स्वयं या किसी अन्य स्त्रोत के द्वारा करनी होगी। प्रशासनिक मदों पर पोषित संस्था द्वारा किये जाने वाले व्यय के एक भाग पर एक तरह का आवरण लगाया जाएगा। व्यवसायिक लोगों की तनख्वाह के अलावा।
   ii. छोटे सिविल सोसायटी संस्थाओं की संस्थागत सुदृढिकरण।
   iii. विकास व्यवसायिकों के एक बडे दल का निर्माण जो कि शासन, सिविल सोसायटी संस्थाओं तथा समुदाय आधारित संस्थाओं के विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
   iv. नवीन पायलट कार्यक्रमों का निर्माण, जांच व उनका क्रियान्वयन।
   v. गरीब व हाशिये में बसे समुदाय का मानव विकास व आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण, जिसमें नवीन कम लागत के घर, पेयजल व स्वच्छता जैसे मुद्दे शामिल हों।
   vi. ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, राज्य शासन, स्थानिय विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं व समुदाय आधारित संस्थाओं के ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बेहतर गुणवत्ता व परिणामों का कुशलता वर्धन व सहयोग।

3. जिन कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है उन्हें शासन के सभी स्तर पर सरलता व नियमित रूप से शासकीय अनुदानों व केंद्रिय योजनाओं का लाभ मिल सके इस बात का समन्वयन करना।

4. सामाजिक विकास के कार्यक्रमों द्वारा आवश्यक विकास परिवर्तन करने के उद्देश्य में से जो भी सीख मिले उसे प्रसारित करना।

   यहां कार्यक्रम से तात्पर्य उन कार्यक्रमों से है जो कि बी आर एल एफ द्वारा समुदाय अधारित संस्थाओं/ सिविल सोसायटी संस्थाओं तथा अन्य चेरिटेबल व प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य व केंद्र शासन द्वारा प्रमुख उत्थान कार्यक्रमों व योजनाओं में आवश्यक मदद मुहैया कराया जाएगा।

5. आदिवासी समुदायों के सामाजिक, प्राकृतिक वातावरण, संस्कृति व सामाजिक विरासत की सुरक्षा, संरक्षण एवं उत्थान हेतु कार्य करना, कार्य में सहयोग देना तथा प्रोत्साहन देना। बी आर एल एफ के उद्देश्यों को विभिन्न प्रकार से आगे बढाने के लिये तथ्यों को एकत्र करना, उनका दस्तावेज़ीकरण करना व उन्हें उन्नत रूप में प्रसारित करना, जिसमें मौखिक, लिखित, ऑडियो, विडियो, ऑडियो–विजुअल, ऑनलाइन व रंगमंच के माध्यम भी शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिये पुस्तकें, पर्चे, लेख, बुलेटिन, पत्रिकाएं अदि के प्रकाशन, लेखन, प्रयोजन व उत्पादन भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुतियां, सेमिनार, परामर्श, कार्यशाला, प्रदर्शनी अथवा इस तरह के अन्य आयोजन भी किये जा सकते हैं।

6. दीर्घकालीन गरिमामय आजीविका विकास, महिलाओं के लिये व्यापक संभावनाओं को बढाना, आदिवासी समुदायों का प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण व पहुंच को बढाने पर प्रोत्साहन देना। विशेषकर महिलाओं के लिये प्राकृतिक संसाधनों को वहन करने की क्षमता का बढाना। प्रभावी, जवाबदेह, पारदर्शी प्रशासन व स्वशासी संस्थानों का निर्माण। जो की मज़बूत और प्रभावशाली मानक व सेवाओं का मांग करती व्यवस्था, युवाओं के लिये नए अवसर व ऐसे कई अन्य परिणाम संस्था के उद्देश्यों में शामिल हैं।

7. कार्यक्रम की लागत व परिणामों के बीच के अंतर को घटाना, ज़मीनी स्तर पर शासकीय संस्थाओं में लोकतंत्र को मजबूत करना। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रभावशालीता को बढाना। कमियों / खामियों को दूर करना, संघर्ष में उलझे क्षेत्रों में सम्मिलित विकास व शांति को प्रोत्साहित करना।

8. आरंभिक स्तरपर मध्यभारत के उन आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस करना, जिन जनपदों में पर्याप्त आदिवासी जनसंख्या न्यूनतम 20 प्रतिशत हो। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात के लगभग 190 जिलों में करीब 1077 जनपद शामिल किये गए है। यह कोई सीमित सूची नहीं है, यदि बी आर एल एफ के द्वारा आवश्यक समझा गया तो विचार विमर्श के बाद इस सूची को विस्तृत किया जा सकता है।

9. ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों, राज्यों, जिलों या जनपदों का सुझाव मिलने पर बी आर एल एफ आने वाले वर्ष में आवश्यकता अनुसार स्पष्ट न्यायसंगत व व्यवहारिक रणनीति के साथ अपने कार्यक्षेत्र का प्रसार कर सकता है।

10. वित्तिय सहयोग हेतु अपील एवं आवेदन जारी करना एवं संस्थापन की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुदान के रूप में नगद, संपत्ति या मानव श्रम को स्वीकार करना।

11. संस्थापन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों एंव गतिविधियों का संचालन करना जिससे आय अर्जित की जा सके, उन गतिविधियों एवं सेवाओं की अनुमति नहीं है जिससे संस्थापन के उद्देश्यों के साथ विरोध की स्थिति पैदा हो।

12. एक प्रक्रिया के तहत पारदर्शी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं से परिपूर्ण एक ढांचे का निर्माण करना और उसे स्थापित करना संस्था के भविष्य के उद्देश्यों में से एक है।

13. ज़मीनी स्तर पर सिविल सोसायटी संगठन को जन सशक्तीकरण की ओर किये जा रहे प्रयासों को समर्थन देना व उन्हें दीर्घकालीन सामुदायिक संस्थानों के रूप में निर्मित करना।

14. क्रीयन्वयन की व्यवस्थाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारना, ज़मीनी स्तर पर जागरूकता को बढाना, समुदाय आधारित संस्थाओं व स्थानीय शासकीय संस्थानों को सशक्त करना, शासकीय संसाधनों को प्रभावशाली तरीके से वितरित करना, तथा शासकीय व्यवस्थाओं को ज़मीनी स्तर पर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होने के लिये समर्थ करना।

15. सिविल सोसायटी संस्थाओं, समुदाय आधारित संस्थाओं व पंचायतीराज संस्थाओं के संस्थागत नेटवर्क मानव संसाधनों को मज़बूत करने के लिये रूपरेखा का निर्माण करना व व्यवस्था को क्रियान्वित करना तथा एक ऐसे मंच का निर्माण करना जिससे की वह और अधिक सबल बन सके।

16. नए विषय, क्षेत्र की समस्याओं और प्रस्तावों का सुझाव देना जिन पर बी आर एल एफ अपने साझेदारों के साथ कार्य कर सके व नेतृत्व कर सके।

17. संस्थापन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उचित माध्यमों के द्वारा वित्तिय एव अन्य संसाधनों को प्राप्त करना। उचित माध्यम से तात्पर्य, संस्थानों, बैंक जैसे नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आदि पीएसयू, कॉरपोरेट क्षेत्र / सिविल सोसायटी / सामान्य सामाजिक संस्थाएं, मानवप्रेमी व्यक्तिगत भी शामिल हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पोषक संस्थाएं व परोपकारी संस्थाएं। जैसा कि संसाधनों को एकत्र करने के लिये प्रचलित है, सभी शासकीय निकासी व अनुमति को प्राप्त किया जाएगा।

18. चुने गए जनपदों में निवास कर रहे लोगों के लिये निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना।

i. सम्मान के साथ दीर्घकालीन आजीविका विकास।
ii. संसाधनों पर नियंत्रण व पहुंच को बढाना।
iii. संसाधनों को संभालने की क्षमता को बढाना।
iv. उत्तरदायी, जवाबदेह, पारदर्शी प्रबंधन व स्वशासी संस्थान।
v. शासकीय कार्यक्रमों का बेहतर प्रदर्शन।
vi. मज़बूत, प्रभावशाली और सहभागी समुदाय आधारित संस्थाए।

ऐसी सभी गतिविधियों का निर्वहन करना जो संस्था के उद्देश्यों में लाभदायक, आवश्यक, सहायक तथा अकस्मात या प्रसंगवश हों.

विषयगत फोकस / केंद्र

बी आर एल एफ ज़मीनीस्तर के सभी कार्यक्रमों को मदद करने की कोशिश करेगा जिनका व्यापक उद्देश्य बैंक व अनगिनत शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का लाभ लेना है। बी आर एल एफ उन सभी प्रस्तावों को मदद करेगा जो कि बैंक व शासकीय योजनाओं के द्वारा लाभ उठाना चाहते हैं, ताकि शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यवहन को नवीनता देते हुए उसे बेहतर बनाया सकें।

हालांकि बी आर एल एफ सीधे तौर पर कार्यक्रम संबंधी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं करेगा अपितु बीआरएलएफ क्षेत्र आधारित कार्यक्रम गतिविधियों को वित्तिय सहायता हेतु राज्य शासन के साथ समन्वय एवं समझौता स्थापित करेगा।

कार्य के विषयगत विषयवस्तु में जो सहयोग किया जाएगा उसमें निम्न बातें शामिल होंगी। हालांकि यह पूर्ण रूप से सीमित नहीं है।

- जलग्रहण विकास।
- सामूहिक संसाधन प्रबंधन जिसमें प्रमुख रूप से भू–जल प्रबंधन, वन प्रबंधन व सहभागी सिंचाई प्रबंधन।
- दीर्घकालीन आजीविका विकास जिसमें प्रमुख रूप से कृषि, डेयरी, मछलीपालन व वन आदि शामिल हैं।
- कृषि उत्पादों, गैर टिंबर वन उत्पादों आदि में गुणवत्ता वृद्वि।
- कौशल विकास
- समुचित निवास सुधार। जिसमें गृह निर्माण, पेयजल, स्वच्छता, ठोस व तरल अपशिष्ट / वेस्ट प्रबंधन आदि भी शामिल है।
- खाद्य व पोषण संरक्षण।
- स्थानिय संस्थाओं में आदिवासी नेतृत्व को बनाना व बढाना, विशेष कर पंचायतों, स्वयंसहायता समूहों, जेएफएमसी, समुदाय आधारित संस्थाओं, औपचारिक व अनौपचारिक उत्पादक समूहों में कार्यरत महिलाओं में।
- परियोजना प्रतिभागी, शासकीय व पंचायती कार्यकारीयों का कुशलता निमार्ण।
- विकास कार्यक्रमों के हितग्राहियों के बीच सामाजिक लामबंदी व जागरूकता बढाना।
- व्यवसायिक मानव संसाधनों के दल का विकास करना जो उक्त सभी क्षेत्रों में कार्यरत होंगे।
- दस्तावेज़ीकरण। (अन्य आजीविका हस्तक्षेप के रूप में)

वे कार्यक्रम जिनमें उक्त विषयगत क्षेत्र ही प्रतिबिंबित होंगे, इस बात की ज्यादा संभावना है कि ऐसे कार्यक्रम बी आर एल एफ द्वारा अधिक समर्थित होंगे।

भैगोलिक केंद्र / फोकस

बी आर एल एफ का प्रारंभिक फोकस मध्यभारत के आदिवासी बहुल क्षेत्र पर होगा जो कि मुख्य रूप से ऐसे जिलों पर केंद्रित होगा जहां 20 प्रतिशत से अधिक आदिवासी समुदायों का निवास हो। इनमें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट, राजस्थान व गुजरात के 1077 उप जिले या जनपद, 190 जिले शामिल हैं। आरंभिक फोकस जनपद / उपजिलों पर किया जाएगा क्योंकि भारत में आदिवासी समुदायों का निवास जिला स्तर से अधिक जनपद स्तर पर अधिक है तथा इस दिशा में विकास व शासकीय प्रक्रिया को मिलाकर व उसके लाभ को प्राप्त करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि जनपद स्तर पर केंद्रीत किया जाए।

इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि बी आर एल एफ तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच 13 जनवरी 2014 को एक एमओयू तय व स्वीकृत किया गया, जिसमें भारत सरकार ने यह तय किया था कि बी आर एल एफ को 500 करोड रूपये कॉर्पस फंड के रूप में अनुमोदित किये जाएंगे। वित्तीय व्यय समिती की शर्त के मुताबिक यह अनुदान 2 भागों में प्रवाहित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार व लोक हितेसी फाउंडेशन की ओर से भी अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुसारणिका I में एमओयू संलग्न है।

बी आर एल एफ शासन

बी आर एल एफ की आम समिती व कार्यकारी समिति में केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधी, प्रशासनिक उच्च अधिकारी, सिविल सोसायटी व कॉरपोरेट क्षेत्र, अर्थिक संस्थानों, जनसेवा क्षेत्र व मानवीय फाउंडेशनों के प्रमाणित अनुभवी, प्रतिबद्ध व बी आर एल एफ के उद्देश्यों से समर्थन रखने वाले सदस्य हैं।

पारदर्शिता व जवाबदेही

पारदर्शिता व जवाबदेही के उच्च मापदंड स्थापित करने के लिये बी आर एल एफ पूरी तरह से अपने लेखा कार्यों व गतिविधियों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट व ऑडिट रिपोर्ट को अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित करेगा। फाउंडेशन पूरी सक्रियता व स्वैच्छा के साथ सभी संबद्ध जानकारियों को सूचना के अधिकार एक्ट 2005 के तहत मुहैया कराएगा। बी आर एल एफ इस बात के लिये भी उत्तरदायी होगा कि उसका वित्तिय अंकेक्षण नियंत्रण महालेखा परिक्षक द्वारा किया जाएगा।

2013 – 2014 के दौरान संपन्न की गई गतिविधियां :

1. बी आर एल एफ के द्वारा दो अलग बैंक खाते खोले गए हैं जिसमें से एक खाते में भारत सरकार की ओर से प्राप्त कॉरपस राशि व दूसरे खाते में एफसीआरए (फॉरेन कॉन्ट्रीबियूशन रेगुलेशन एक्ट) के अंतर्गत प्राप्त हुई निधि को संरक्षित किया गया है। दोनों खातों के विवरण इस प्रकार हैं :

   a. **भारत सरकार की ओर से प्राप्त कॉरपस निधि :**

   खाते का नाम : भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन
   खाता क्रमांक : 000394600000384
   खाता प्रकार : बचत
   बैंक का पता : यस बैंक लिमिटेड
   प्लॉट नंबर – 11/46 शॉपिंग सेंटर
   डिप्लोमेटिक एनक्लेव, मालछा मार्ग, नई दिल्ली – 110021

   b. **एफसीआरए रजिस्ट्रेशन**

   खाते का नाम : भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन
   खाता क्रमांक : 000393900000039
   खाता प्रकार : बचत
   बैंक का पता : यस बैंक लिमिटेड
   प्लॉट नंबर – 11/46 शॉपिंग सेंटर
   डिप्लोमेटिक एनक्लेव, मालछा मार्ग, नई दिल्ली – 110021

2. बी आर एल एफ को पैन नंबर/स्थायी खाता क्रमांक भी आवंटित किया गया है। बी आर एल एफ का स्थायी खाता क्रमांक AACAB2971N है।

3. भारत सरकार की ओर से 5 मार्च 2014 को 200 करोड रूपयों का कॉरपस निधि प्रदान की गई जो कि यस बैंक लिमिटेड के खाता क्रमांक : 000394600000384 में जमा की गई।

वर्ष 2013 – 14 में बी आर एल एफ का वित्तीय अंकेक्षण "एवा एंव असोसिएट्सचार्टर्डअकांउंटेन्ट्स" के द्वारा किया गया, जो कि भारतीय वित्तिय अंकेक्षणनियंत्रण महालेखापरिक्षक कार्यालय के तहत सूचिबद्ध है। अनुसारणिका II में अंकेक्षणरिपोर्ट व अंकेक्षण विवरण संयुक्त रूप से संलग्न है।

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA
AND
BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

This MoU is being entered into between:

The Ministry of Rural Development, Government of India (to be called MoRD hereafter)

And

Bharat Rural Livelihoods Foundation, an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860 having registration number S/ND/351/2013 and registered office at 38-A Krishi Bhawan, New Delhi (to be called BRLF hereafter)

On this 13th day of January (month) in the year 2014

Whereas the Government of India has decided to

A. Set up Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) as an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860
B. Release Rs. 500 Crore for creating the corpus of the new Society, in two tranches subject to conditions laid down by Expenditure Finance Committee

Whereas BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women, particularly in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning.

Whereas MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

Whereas through setting up of BRLF, the MoRD desires to look at a new model of partnership wherein Government proactively engages with private philanthropies, public and private sector undertakings (as part of their corporate social responsibility) as well as other stake-holder groups to raise resources to support and scale up proven interventions ofCivil Society Organisations.

And whereas the Government of India decided that the first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be provided to BRLF at the time of its formation and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be provided after two years subject to fulfilment of certain conditions.

NOW THE MoU STANDSAS FOLLOWS:

1. The first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be released to BRLF by the MoRD immediately upon signing of this MoU between the two parties and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be released after two years on fulfillment of the following conditions:.

1. The corpus must be managed by BRLF and invested following prudential financial norms under competent advice. No expenditure should be made from the corpus itself and only the income arising out of the corpus can be utilized to fulfill the objectives of BRLF

2. In the initial years, BRLF may focus on blocks that have at least 20 percent tribal population from the tribal regions of Central India, with preference where possible to areas of higher tribal population. However, BRLF should be open for pan-India implementation also, in later years.

3. BRLF needs to frame its corpus management policy, grant making policy, human resources policy etc. within a definite time frame and well before release of the second tranche.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

4. To achieve the objectives of BRLF for upscaling civil society action in collaboration with the Government, the most important component of the grant support to Non-Government Organisations /Civil Society Organisations by BRLF will be to meet their cost of additional professionals and institutional costs of supporting the professionals. In this respect, BRLF should bear no more than 80% of the costs. The rest has to be sourced by the grantee NGO/CSO from own or other sources. A cap on the proportion of funds to be spent on administrative matters should be placed by BRLF (other than salary of professionals).

5. The evaluation criteria for assessing the impact of BRLF should be firmed up at the beginning itself so as to enable an independent assessment of the impact at the end of the XII Five Year Plan. The Government will undertake a review of BRLF after five years and in case the outcomes are not forthcoming as projected, the Government will be free to take back the grant and advise dissolution of BRLF.

6 One of the expectations from BRLF is that the experiences of resolving the problems of the tribal and other poor communities should throw up recommendations to the Government on the changes required in programmes and policies. BRLF will periodically send its recommendations to the Government in appropriate ways.

7. For the release of the 2nd tranche of corpus fund amounting to Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore), the following are the conditions to be met by BRLF in addition to the above:

   a. Completion of the process of hiring of the CEO and other core staff
   b. Formulation of basic operating policies, including grant approval & monitoring, HR policy etc
   c. Conclusion of agreements with States regarding flow of programme funds to projects
   d. Selection of first batch of projects and start of work on ground

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

e. The CSOs supported by BRLF should be able to reach out to at least 1,00,000 families

f. At least Rs. 100 Crore (Rupees One Hundred Crore) of private contribution should be mobilized either through corpus contribution or through annual grants or through co-financing by other donors

g. Improvement in scheme delivery should be documented

h. Regularity of Board meetings in accordance with the letter and spirit of Byelaws of BRLF

i. Proper management of Corpus with competent advice

2. Through this MoU, the MoRD commits to provide the following support to BRLF:

1. Immediately upon signing of this MoU, MoRD will transfer first tranche of its corpus support of Rs. 200 crore to BRLF
2. MoRD will make every endeavor to foster and facilitate effective working relationship between the State Governments, BRLF and Civil Society Organisations supported by BRLF
3. MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes
4. MoRD will support BRLF's endeavor to raise financial resources from non-government sources including private philanthropies, public and private sector undertakings, CSR initiatives etc.
5. Upon fulfilment of conditions laid down in this MoU, MoRD will transfer second tranche of its corpus support of Rs. 300 crore to BRLF

3. Reporting:

BRLF will report to the MoRD on an annual basis by submitting its audited financial report; corpus/other funds mobilization, investment and utilization report and narrative annual report.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

4. Visibility:

BRLF should mention the following in its communications and on its letter-head:

"An independent society set up by the Government of India to upscale civil society action in partnership with Government"

5. Indemnity

BRLF and MoRD shall fully indemnify each other of all statutory liabilities arising due to their own failure to comply with statutory obligations. In addition to this general indemnity, BRLF and MoRD shall completely absolve each other from any other liability issues that may be raised against it by any of its clients /customers /partners

6. Force majeure

1. For the purpose of this MoU, 'force majeure' means an event which is beyond the reasonable control of a party, either BRLF or MoRD and which makes a party's performance regarding its obligations hereunder impossible or so impracticable as reasonably, to be considered impossible in the circumstances and includes, but is not limited to war, riots, civil/disorder, earthquake, fire, explosion, storm, flood and other adverse weather conditions, strikes lock-outs of other similar action which are not within the power of the party invoking "force majeure" to prevent confiscation or any other action by the other party.
2. The failure of any party, either BRLF or MoRD, to fulfill any of its obligations hereunder shall not be considered to be breach of, or default under this MoU in so far as such inability arises from an event of force majeure, provided that the party affected by such event should take all reasonable precautions due care and reasonable alternative measures to the satisfaction of the other party, all with the objectives of carrying out the terms and conditions of this MoU.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

3. In the event of a force majeure, BRLF and MoRD shall consult with each other, with a view to agreeing on appropriate measures to be taken under the circumstances.

7. Disputes and arbitration:

Any dispute between BRLF and MoRD on any matter that has relevance to the smooth and effective functioning of BRLF and achieving the purposes for which BRLF is set up, shall be settled through mutual discussion. In case they are not able to resolve the dispute among themselves, the Secretary, Rural Development, Government of India will act as the Arbitrator.

Signed on 13 th day of January in the year 2014 by

Designated Official on behalf of

Bharat Rural Livelihoods Foundation

Signature:

Name: T. Vijay Kumar

Seal CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

Witness

Signature:

Name: Naval Kishor Gupta

Address: 19/414, Sundaram Khand
Sector-19, Vasundhara,
Ghaziabad, UP-201012

Designated Official on behalf of

Ministry of Rural Development

Government of India

Signature

Name एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary

Seal ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Witness

Signature:

Name: P.S. PRASANNA KUMAR

Address: पी एस प्रसन्ना कुमार
P. S. Prasanna Kumar
निजी सचिव/Private Secretary
ग्रामीण विकास मंत्रालय/Min. of Rural Development
भारत सरकार/Govt of India
कृषि भवन नई दिल्ली-1/Krishi Bhavan, New Delhi-1

AVA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

4F, Gopala Tower, 25, Rajendra Place
New Delhi -110 008 (India)
Tel. : +91-11-25868593 - 94
Fax : +91-11-45040855
E-mail : ava@avaca.in

Independent Auditors' Report

To The Members of
Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2014, the Income and Expenditure Account, Receipt and Payment Account for the year ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Company in accordance with the accounting practices followed as per the guidelines prescribed by the Government of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Society's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Society's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion

Opinion

We further report that we have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit. In our opinion proper books of accounts have been kept by the Society as far as appears from our examination of those books. We also report that the annexed statements of accounts are in agreement with the said books of accounts.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read with the schedules thereon give a true and fair view in accordance with the accounting principles generally accepted in India:

a. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2014.

b. In the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus of the period ended on that date.

c. In the case of Receipt and Payment Account, of the cash flows during the period.

For AVA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 004017N

(CA Avineesh Matta)
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 25.09.2014

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2014

Amount in Rs.

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	2013-14
Corpus Fund	A	2,000,000,000
Reserve & Surplus	B	14,322,493
Total (Rs.)		**2,014,322,493**
ASSETS		
Current Assets, Loans and Advances	C	
Cash & Bank Balance		2,014,322,493
TOTAL (Rs.)		**2,014,322,493**
Significant Accounting Policies	F	
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	G	

As per our report of even dated attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN : 004017N

CA Avineesh Matta
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 25.09.2014

AVA & ASSOCIATES * CHARTERED ACCOUNTANTS * NEW DELHI

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Anil Subramaniam)
Chief Finance Officer

अनिल सुब्रमनियम / ANIL SUBRAMANIAM
उप सचिव / Deputy Secretary
भारत सरकार / Govt. of India
ग्रामीण विकास मंत्रालय/M/o Rural Development
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi

(Zulfiqar Haider)
Chief Executive Officer

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

Amount in Rs.

Receipts		2013-14
Opening Balance		
Cash		-
Bank Balance		-
a. Donation from Nimesh Sumati	1,000,000	
b. Corpus Grant from Ministry of Rural Development, Government of India (MORD)	2,000,000,000	2,001,000,000
Interest received on Saving Bank Account		13,322,493
TOTAL		**2,014,322,493**
Closing Balance		
a) Cash		-
b) Bank		2,014,322,493
TOTAL		**2,014,322,493**

As per our report of even date attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN : 004017N

CA Avineesh Matta
(Partner)
M. No. : 083054
Place: New Delhi
Date: 25.09.2014

AVA & ASSOCIATES * NEW DELHI * CHARTERED ACCOUNTANTS

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Anil Subramaniam)
Chief Finance Officer

अनिल सुब्रमनियम / ANIL SUBRAMANIAM
उप सचिव / Deputy Secretary
भारत सरकार / Govt. of India
ग्रामीण विकास मंत्रालय/M/o Rural Development
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

Amount in Rs.

INCOME	Sch	Rs.	2013-14
Grants, Subsidies & Donations	D		
i. Donation		1,000,000	
			1,000,000.00
Other Income	E		13,322,493.15
TOTAL			14,322,493.15
EXPENDITURE			
Expenditure		-	-
Excess of Income over Expenditure			14,322,493.15
TOTAL			14,322,493.15
Significant Accounting Policies	F		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	G		

As per our report of even date attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN:004017N

CA Avineesh Matta
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 25.09.2014

AVA & ASSOCIATES ★ NEW DELHI ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Anil Subramaniam)
Chief Finance Officer

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

अनिल सुब्रमनियम / ANIL SUBRAMANIAM
उप सचिव / Deputy Secretary
भारत सरकार / Govt. of India
ग्रामीण विकास मंत्रालय/M/o Rural Development
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(Amount - Rs.)

	Rs.	2013-14
SCHEDULE A - Corpus Fund		
Contribution received towards Corpus Fund by Ministry of Rural Development, Government of India	2,000,000,000	
Closing balance		2,000,000,000
TOTAL		**2,000,000,000**
SCHEDULE B - Reserve & Surplus		**2013-14**
a. Surplus		
Opening Balance	-	
Add: Excess of Income over Expenditure during the year	14,322,493	
Closing Balance as on 31.03.2014	14,322,493	14,322,493
Total		**14,322,493**
SCHEDULE C - Current Assets, Loan & Advances and Other Assets		**2013-14**
a. Current Assets		
Cash & Bank Balances:		
Cash in Hand		-
Bank Balance in Saving Account with Yes Bank at Chanakyapuri Branch, New Delhi		2,014,322,493
Total (A)		**2,014,322,493**
b. Loan & Advances and Other Assets		-
Total (B)		-
GRAND Total (A+B)		**2,014,322,493**

SCHEDULE D. Grants, Subsidies & Donations		
i. Donation from Nimesh Sumati	1,000,000	
		1,000,000
Total Grants		**1,000,000**

SCHEDULE E. Other Incomes		
Saving Bank Interest		**13,322,493**
Total		**13,322,493**

SCHEDULE-F

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

1. Legal Status and Operation:

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been promoted by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013.

Envisaged as supporting CSO projects focused on tribal, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering nine states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat, its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India has released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores will be released after two years on fulfilment of conditions prescribed in the MOU. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfil the objectives of the society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

2. Summary of Significant Accounting policies:

2.1 Accounting Convention

These statements of accounts have been prepared under the historical cost convention, without any adjustment to the effect of inflation.

2.2 Basis of preparation

The financial statement has been prepared following cash basis of accounting.

2.3 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as per AS-12 – Accounting for Government Grants issued by Institute of Chartered Accountants of India.

i. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus shall be utilized to fulfil the objectives of BRLF.
ii. Grants received for specific purposes are utilized for the purpose of its release.

iii. Grants utilized to the extent of and in accordance with the grant conditions and project objectives are treated as Income in the Income & Expenditure Account.
iv. Unutilized grants are treated as Liabilities in the Balance sheet.

2.4 Income Recognition

Interest on saving bank is recognized on receipt basis.

2.5 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society shall fulfill the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act..

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

AVA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

(Anil Subramaniam)
Chief Finance Officer

अनिल सुब्रमनियम / ANIL SUBRAMANIAM
उप सचिव / Deputy Secretary
भारत सरकार / Govt. of India
ग्रामीण विकास मंत्रालय/M/o Rural Development
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi

(Zulfiqar Haider)
Chief Executive Officer

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

SCHEDULE-G

CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS (FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS)

I. In the opinion of the Management Current Assets are approximately of the value stated if realized in the ordinary course of business except otherwise stated.

II. The society has not procured any goods or services during audit period. No fixed assets were acquired by the Society during the year 2013-14.

III. During the year Society has received Rs. 10 Lakh as Donation from Mr. Nimesh Sumati, to be used for the purposes of achieving of Society's objectives.

IV. Audit fees of Rs. 18000/- and applicable service tax payable for the year 2013-14 will be accounted for in the year of payment.

V. The present being the first year of operations, no previous year figures is reported.

VI. Figures have been rounded off to nearest rupees.

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Anil Subramaniam)
Chief Finance Officer

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

अनिल सुब्रमनियम / ANIL SUBRAMANIAM
उप सचिव / Deputy Secretary
भारत सरकार / Govt. of India
ग्रामीण विकास मंत्रालय/M/o Rural Development
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

भारत रूरल लाइवलीहुडस फाउंडेशन
सी32, II फ्लोर, रतना विलास
नीति बाग, नई दिल्ली – 110049
www.brlf.in